



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ११, अंक १२]

बुधवार, मार्च २६, २०२५/चैत्र ५, शके १९४७

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक २२

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)
वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ मार्च २०२५.

क्रमांक : जीवीका-२०२४/प्र.क्र.६३/नापु-२८, ग्राहक बाबी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडून असाधारण राजपत्र, भाग II- खण्ड ३, उप-खंड (ii) मध्ये दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२५ रोजी प्रकाशित झालेली अधिसूचना खालीलप्रमाणे पुनःप्रकाशित करण्यात येत आहे.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग).

आदेश

का.आ. ९०१ (अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १०) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के आदेश असाधारण, भाग II, खण्ड-३, उप- खण्ड (ii) में दिनांक २४ जून २०२४ के का.आ.२४२८ (अ) के माध्यम से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त आदेश में, पैराग्राफ २(i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायगा ।

२(i) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं के साथ दिनांक ३१ मार्च, २०२५ तक की अवधि के लिए गेहूं:

- व्यापारी/थोक विक्रेता : २५० मीट्रिक टन ;
- रिटेलर : प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए ४ मीट्रिक टन।

(१)

● बिग चैन रिटेलर : प्रत्येक आउटलेट के लिए ४ मीट्रिक टन, बशर्ते कि उनके सभी आउटलेट और डिपो पर स्टॉक की अधिकतम मात्रा (आउटलेटों की कुल संख्या से ४ गुणा) मीट्रिक टन हो।।

● प्रोसेसर्स : मासिक स्थापित क्षमता के ५०% मात्रा को अप्रैल, २०२५ तक शेष महिनों से गुणा, के बराबर

उपर्युक्त के अनुसार संबंधित विधिक इकाईयां, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (<https://evegoils.nic.in/wsp/login>) पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी और यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से १५ दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाएंगे।

[फा. सं. ३/१/२००७-नीति-III]

शिखा सी,
संयुक्त सचिव.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

Order

New Delhi, the 20th February, 2025

S.O. 901(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India in the Department of Food and Public Distribution published in the *Gazette of India*, Extraordinary, Part (II), Section-3, Sub Section (ii) *vide* S.O.2428(E) dated 24th June 2024, namely:—

In the said Order, Paragraph 2(i) shall be replaced as under:

2(i) Wheat for a period upto 31st March 2025 with following stock limits for all States and Union Territories:

- Traders/Wholesaler : 250 MT.;
- Retailer : 4 MT. for each Retail outlet ;
- Big Chain Retailer : 4 MT. for each outlet subject to maximum quantity of (4 multiplied by total number of outlets) MT. stock at all their outlets and Depots put together.
- Processors : 50% of Monthly Installed Capacity (MIC) multiplied by remaining months till April, 2025.

Respective legal entities, as above, shall declare the stocks position on the portal (<https://evegoils.nic.in/wsp/login>) of Department of Food and PD and in case the stocks held by them are higher than the prescribed limits, then they shall bring the same to the prescribed stock limits within 15 days of issue of this notification.

[F. No. 3/1/2007 Py-III]

SHIKHA C,
Joint Secretary.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

ता. मा. कोळेकर,

शासनाचे सहसचिव.